

करेंट अफेयर्स वार्षिकी 2025

जनवरी 2024 से अब तक
का दृढ़ पॉइंट कवरेज

400+ MCQs का
टॉपिकवाइज कवरेज

केन्द्र सरकार, राज्यों के
मुख्यमंत्री तथा पदाधिकारी

1000+
Revision बुलेट्स



UPSC, राज्य PSCs, NDA/NA,
CDS, SSC (CGL, MTS, CHSL,
कांस्टेबल) तथा अन्य राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय प्रतियोगी
परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी

डी. गुकेश बने सबसे युवा चेस वर्ल्ड चैम्पियन • डोनाल्ड ट्रम्प बने अमेरिकी
राष्ट्रपति • G20 शिखर सम्मेलन 2024 • ICC T20 विश्व कप 2024
नोबेल प्राइज 2024 • UNESCO विश्व धरोहर समिति का 46वाँ सत्र
आठ राज्यों में विधानसभा चुनाव • आम चुनाव 2024
आम बजट 2024-25



टॉपर्स द्वारा प्रशंसित तथा विगत
19 वर्षों से सर्वाधिक बिकने वाली पत्रिका
₹195.00

करेण्ट अफेयर्स वार्षिकी 2025

जनवरी 2024 से अब तक
का दृढ़ पॉइण्ट कवरेज

400+ MCQs का
टॉपिकवाइज कवरेज

केन्द्र सरकार, राज्यों के
मुख्यमन्त्री तथा पदाधिकारी

1000+
Revision बुलेट्स

₹199 का Online Test पैकेज फ्री

करेण्ट अफेयर्स
(Jan-Dec 24)

100

Total Tests

Attempt Test

View

Price
₹199

Validity
6 Months

Coupon Code: **CAYEA25**

पैकेज की विशेषताएँ

- ✓ Detailed Analysis रिपोर्ट
- ✓ Mock Test को Multiple Times Attempt (Re-Attempt) कर सकते हैं
- ✓ सभी प्रश्नों के Detailed Solutions भी

Login हेतु निर्देश



- www.examwitharihant.com पर Login करना होगा।
- इसके बाद Book Code/Coupon Code पर Click कर दिया गया Code डालना होगा।

Download App



arihant

समसामयिकी महासागर

अन्दर के पृष्ठों में

❖ राष्ट्रीय परिदृश्य 3-38

- योजना/कार्यक्रम
- शिक्षा क्षेत्र
- रेलवे क्षेत्र
- कला एवं संस्कृति
- Exam शूटर्स
- सम्मेलन/बैठक
- ऐप्प/पोर्टल 2024
- सूचकांक/रिपोर्ट 2024
- महत्वपूर्ण विधेयक 2024

❖ विश्व परिदृश्य 39-68

- नव-नियुक्त प्रधानमन्त्री 2024
- नव-निर्वाचित राष्ट्रपति 2024
- Exam शूटर्स

❖ भारत एवं विश्व 69-82

- Exam शूटर्स

❖ अर्थव्यवस्था एवं बैंकिंग 83-102

- RBI घटनाक्रम
- कॉर्पोरेट क्षेत्र
- सूचकांक/रिपोर्ट/रैंकिंग 2024
- Exam शूटर्स
- बैंकिंग क्षेत्र
- सम्मेलन/बैठक

❖ राज्य परिदृश्य 103-128

- Exam शूटर्स

❖ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी 129-138

- कम्प्यूटर/संचार प्रौद्योगिकी
- Exam शूटर्स

❖ अन्तरिक्ष प्रौद्योगिकी 139-146

- ISRO गतिविधियाँ
- NASA घटनाक्रम
- Exam शूटर्स

❖ रक्षा एवं प्रतिरक्षा 147-156

- मिसाइल परीक्षण
- सेवा में शामिल/सेवा मुक्ति
- सैन्य अभ्यास
- Exam शूटर्स

❖ स्वास्थ्य एवं पोषण 157-164

- Exam शूटर्स

❖ कृषि, पर्यावरण एवं जैव-विविधता 165-174

- Exam शूटर्स

❖ खेल पैनोरमा 175-188

- खेल समाचार
- Exam शूटर्स

❖ पुरस्कार एवं सम्मान 189-204

- राष्ट्रीय
- अन्तर्राष्ट्रीय
- Exam शूटर्स

❖ न्यूज लाइन 205-226

- राष्ट्रीय
- अन्तर्राष्ट्रीय
- Exam शूटर्स

❖ 1000+ रिविजन Bullets 227-240

❖ प्रैक्टिस PYQs 241-252

❖ नवीनतम कौन क्या है 253-256

❖ इन्फोग्राफिक्स 2024 257-272

- डी. गुकेश-सबसे युवा चेस वर्ल्ड चैंपियन
- PAN 2.0 परियोजना
- आठ राज्यों में विधानसभा चुनाव
- 19वाँ G20 शिखर सम्मेलन 2024
- 16वाँ BRICS शिखर सम्मेलन 2024
- नोबेल पुरस्कार 2024
- 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2024
- ओलम्पिक्स 2024
- लोकसभा चुनाव 2024
- 96वें ऑस्कर पुरस्कार 2024
- प्रधानमन्त्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना
- NSIL GSAT-N2 मिशन
- एकीकृत पेन्शन योजना
- ICC T20 वर्ल्ड कप 2024
- IPL 2024
- भारत रत्न 2024

प्रकाशक : पायल जैन

चेयरमैन : वाई.सी.जैन

सम्पादक : संजय सागर

पब्लिशिंग मैनेजर : अमित वर्मा

प्रोजेक्ट मैनेजर : अमित त्यागी

कवर एवं लेआउट : सलमान शेख, अंकित प्रजापति,
राकेश रावत

मुख्य पेज डिजाइनर : प्रदीप कुमार, राजीव सैनी,
हारून खान

टाइप सैटिंग : नितिन कुमार, हिमांशु

कार्यालय

प्रधान कार्यालय

अरिहन्त मीडिया प्रोमोटर्स

कालिन्दी, टीपी नगर, मेरठ

फोन : 0121-2401479, 2512970

फैक्स : 0121-2401648

वितरण/व्यावसायिक कार्यालय

अरिहन्त मीडिया प्रोमोटर्स

4577/15, अग्रवाल रोड, दरिया गंज, नई दिल्ली-2

फोन 011-23272342

इन्क्वायरी : 0121-4030840

ई-मेल : arihantmedia.amit@gmail.com

वेबसाइट : www.arihantbooks.com

© प्रकाशक

अरिहन्त मीडिया प्रोमोटर्स के लिए श्रीमती पायल जैन द्वारा
प्रकाशित एवं मुद्रित अरिहन्त पब्लिकेशन्स (इण्डिया) लिमिटेड,
मेरठ से मुद्रित

इस पत्रिका में प्रकाशित सभी लेख उनके रचनाकारों के स्वयं के हैं,
तथा वे किसी भी स्थिति में उनसे सम्बन्धित सरकारी या
गैर-सरकारी संस्था या करेण्ट अफेयर्स.com सम्पादक मण्डल
के विचार नहीं हैं।

इस पत्रिका में प्रकाशित सूचनाएँ, समाचार, ज्ञान एवं तथ्य पूरी
तरह से सत्यापित किए गए हैं। यदि कोई जानकारी या तथ्य
गलत प्रकाशित हो गया है तो प्रकाशक, सम्पादक या मुद्रक उससे
किसी व्यक्ति-विशेष को पहुँची क्षति के लिए जिम्मेदार नहीं हैं।

किसी भी स्थिति में न्यायिक क्षेत्र मेरठ (उत्तर प्रदेश) होगा।

करेण्ट अफेयर्स के नियमित अपडेट्स के लिए, हमें फॉलो करें ▶ Examwitharihant

राष्ट्रीय परिदृश्य

राष्ट्रीय स्तर पर वर्ष 2024 में सबसे महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण घटना प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनना रही। इसके अलावा पीएम सूर्य गृह मुक्त बिजली योजना जैसी कई महत्वपूर्ण योजनाएँ भी इसी वर्ष शुरू की गई। केन्द्र सरकार ने इस वर्ष 23वें विधि आयोग का गठन भी किया। तीन नए आपराधिक कानून और नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) भी लागू हुए। कोझिकोड को भारत का पहला 'यूनेस्को सिटी ऑफ लिटरेचर' घोषित किया जाना भी इस वर्ष की एक महत्वपूर्ण घटना रही।



करेंट अफेयर्स
वार्षिकी

एक राष्ट्र, एक चुनाव विधेयक को मंजूरी

- केन्द्रीय मन्त्रिमण्डल द्वारा 13 दिसम्बर, 2024 को एक राष्ट्र, एक चुनाव विधेयक स्वीकृत कर दिया गया, जिसका उद्देश्य स्थानीय, राज्य और लोकसभा चुनाव एक साथ कराना है।
- इसमें चरणबद्ध तरीके से राज्य विधानसभा और लोकसभा चुनाव एक साथ कराने और उसके बाद सौ दिनों के भीतर स्थानीय निकाय चुनाव कराने का प्रस्ताव है।
- यह विधेयक, जिसके लिए भारत के आधे राज्यों से अनुमोदन की आवश्यकता है और जो संविधान के कम से कम पाँच खण्डों में बदलाव करता है, अत्यधिक जटिल है।
- वर्ष 1967 तक, भारत में राज्य विधानसभाओं और लोकसभा के लिए एक साथ चुनाव होते थे। अब केवल चार राज्यों में लोकसभा चुनाव विधानसभा चुनावों के साथ होते हैं।
- समर्थकों का तर्क है कि यह कानून शासन की निरंतरता सुनिश्चित करेगा, चुनाव खर्च को कम करेगा, मतदाताओं की थकान को कम करेगा और मतदान को बढ़ावा देगा।
- तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एके स्टालिन उन विरोधियों में से हैं, जो दावा करते हैं कि यह योजना लोकतन्त्र विरोधी है और क्षेत्रीय दलों को हाशिए पर डाल सकती है।

प्रधानमंत्री मोदी द्वारा अष्टलक्ष्मी महोत्सव का उद्घाटन

- प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 6 दिसम्बर, 2024 को नई दिल्ली के भारत मण्डप में अष्टलक्ष्मी महोत्सव का उद्घाटन किया।
- 6 से 8 दिसम्बर तक आयोजित इस कार्यक्रम में पूर्वोत्तर भारत की जीवंत संस्कृति का जश्न मनाया गया।
- इसका उद्देश्य क्षेत्र के कपड़ा क्षेत्र, पारम्परिक शिल्प कौशल, पर्यटन क्षमता और अद्वितीय जीआई टैग वाले उत्पादों का प्रदर्शित करने के लिए एक गतिशील मंच प्रदान करना है।
- समृद्धि के आठ रूपों के नाम पर आयोजित इस कार्यक्रम में असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैण्ड, त्रिपुरा और सिक्किम की समृद्ध परम्पराओं और विकास का जश्न मनाया गया।

अन्न चक्र शुभारम्भ

- केन्द्रीय मन्त्री प्रल्हाद जोशी ने 5 दिसम्बर, 2024 को 'अन्न चक्र' और SCAN (NFSA के लिए सब्सिडी दावा आवेदन) पोर्टल लॉन्च किया।
- इसका उद्देश्य भारत की 'सार्वजनिक वितरण प्रणाली' (PDS) का आधुनिकीकरण करना और

'राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम' (NFSA) के अंतर्गत सब्सिडी दावों को सुव्यवस्थित करना था।

- इसे वर्ल्ड फूड प्रोग्राम (WFP) और फाउण्डेशन फॉर इनोवेशन एण्ड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर (FITT) के सहयोग से बनाया गया है।

भारतीय संविधान का संस्कृत और मैथिली अनुवाद

- राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 26 नवम्बर, 2024 को नई दिल्ली में भारतीय संविधान के संस्कृत और मैथिली अनुवाद का अनावरण किया।



- यह संविधान दिवस और संविधान अपनाने की 75वीं वर्षगांठ का अवसर था।
- इसका आयोजन उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने किया।
- 'हमारा संविधान, हमारा स्वाभिमान' अभियान, 26 नवम्बर, 2024 को शुरू किया गया।
- भारतीय संविधान 26 नवम्बर, 1949 को अपनाया गया था।
- संस्कृत और मैथिली अनुवाद संवैधानिक सिद्धांतों की गहरी समझ प्रदान करके नागरिकों को सशक्त बनाते हैं।

कैबिनेट ने PAN 2.0 को दी मंजूरी

- आर्थिक मामलों की मन्त्रिमण्डलीय समिति ने PAN और TAN प्रणालियों को डिजिटल बनाने के लिए 26 नवम्बर, 2024 को PAN 2.0 परियोजना को मंजूरी दे दी।
- PAN 2.0 में पुनः आवेदन की आवश्यकता नहीं, डिजिटल उन्नयन, QR कोड एकीकरण, सुव्यवस्थित प्रक्रियाएँ, बेहतर सेवा वितरण जैसी विशेषताएँ हैं।
- इससे करदाता PAN-सम्बन्धी सेवाओं के तीव्र एवं सुरक्षित प्रसंस्करण, सरकारी प्रणालियों में एकीकृत पहचानकर्ता तथा कागज रहित लेनदेन से लाभान्वित होंगे।
- सरकार ने बुनियादी ढांचे के उन्नयन के लिए ₹ 1435 करोड़ आवंटित किए हैं और 78 करोड़ से अधिक PAN कार्ड जारी किए हैं, जिससे 98% करदाताओं को लाभ मिला है।

- PAN 2.0 अनावश्यकताओं को समाप्त करता है, अनुपालन को सुगम बनाता है, तथा एकीकृत डिजिटल व्यवसाय पहचानकर्ता प्रदान करके व्यवसाय दक्षता को बढ़ाता है।

राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन को मंजूरी

- केन्द्रीय मन्त्रिमण्डल द्वारा 25 नवम्बर, 2024 को अनुमोदित भारत के राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन (NMNF) का उद्देश्य शून्य बजट प्राकृतिक खेती जैसी दीर्घकालिक कृषि प्रथाओं को बढ़ावा देना है।
- NMNF का लक्ष्य ग्राम पंचायतों के 15000 समूहों को प्राकृतिक कृषि इनपुट प्रदान करना है, जिसके लिए केन्द्रीय और राज्य आवण्टन सहित ₹ 2481 करोड़ का वित्तीय परिव्यय निर्धारित किया गया है।
- NMNF भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति, गोबर्धन मिशन और प्राकृतिक खेती गलियारे जैसी पिछली पहलों को एकीकृत करता है।
- शून्य बजट प्राकृतिक खेती (ZBNF) एक दीर्घकालिक कृषि पद्धति है जो गाय के गोबर, मूत्र, स्थानीय बीज और जैविक खाद जैसे प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर करती है।

2028 तक बढ़ाया अटल इनोवेशन मिशन

- भारत सरकार ने अटल इनोवेशन मिशन (AIM) को 31 मार्च, 2028 तक बढ़ा दिया है, तथा AIM 2.0 25 नवम्बर, 2024 को लॉन्च किया गया था। इसका उद्देश्य प्रणालीगत अंतरालों को दूर करना तथा उद्यमशीलता परिणामों में सुधार करना है।
- AIM 1.0 का ध्यान अटल टिंकरिंग लैब्स और अटल इनक्यूबेशन सेंटर जैसे आधारभूत नवाचार प्लेटफॉर्म की स्थापना पर केन्द्रित था।
- AIM 2.0 का उद्देश्य ग्रामीण नवाचार केन्द्रों, डीपटेक रिएक्टरों और क्षेत्रीय लॉन्चपैड जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से अन्तराल को भरना एवं पारिस्थितिकी तंत्र की दक्षता को बढ़ाना है।
- AIM 2.0 का उद्देश्य स्थानीय नवाचार केंद्रों के माध्यम से इनपुट बढ़ाना, अटल टिंकरिंग लैब्स का विस्तार करना, मानव पूँजी विकास के माध्यम से सफलता दर में सुधार करना है।

राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन कार्यक्रम का विस्तार

- सरकार 24 नवम्बर, 2024 को घोषित विभिन्न उद्योगों में उपभोक्ता शिकायतों के समाधान में दक्षता में सुधार लाने के लिए अधिक फर्मों को शामिल करने के लिए अपने NCH कार्यक्रम का विस्तार कर रही है।

- यह कार्यक्रम विभिन्न क्षेत्रों की 1000 से अधिक कंपनियों को वास्तविक समय पर शिकायत समाधान प्रदान करता है, जिसका लक्ष्य 30 दिनों के अन्दर समस्याओं का समाधान करना है।
- NCH शिकायत निवारण प्रक्रियाओं को कारगर बनाने के लिए उन्नत प्रौद्योगिकी को लागू कर रहा है, जिसमें AI-संचालित वाक् पहचान और बहुभाषी चैटबॉट शामिल हैं।
- यह कार्यक्रम उपभोक्ता विश्वास को बढ़ाता है, उपभोक्ता अधिकारों का समर्थन करता है, तथा पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देकर व्यावसायिक दक्षता में सुधार करता है।

‘नई चेतना-पहल बदलाव की’ का तीसरा संस्करण

- ग्रामीण विकास मन्त्री शिवराज सिंह चौहान ने 23 नवम्बर, 2024 को नई दिल्ली में लिंग आधारित हिंसा के विरुद्ध एक माह तक चलने वाले अभियान ‘नई चेतना 3.0’ का शुभारम्भ किया।
- इसे 23 दिसम्बर, 2024 तक सभी राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों में लागू किया जाएगा।
- ‘नई चेतना 3.0’ अभियान सामूहिक कार्रवाई को बढ़ावा देकर, जमीनी स्तर पर भागीदारी को बढ़ावा देकर, तथा भारत में महिलाओं के लिए अधिक सुरक्षित, अधिक न्यायसंगत भविष्य का मार्ग प्रशस्त करके लैंगिक हिंसा से निपटता है।
- इस अभियान का उद्देश्य लिंग आधारित हिंसा के बारे में जागरूकता बढ़ाना, कार्रवाई को प्रोत्साहित करना, सहायता प्रदान करना और स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से समुदायों को सशक्त बनाना है।

प्रसार भारती का OTT प्लेटफॉर्म ‘WAVES’ लॉन्च

- प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म ‘WAVES’ को 20 नवम्बर, 2024 को 55वें भारतीय अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में लॉन्च किया गया।
- ‘WAVES’ 65 लाइव TV चैनल, वीडियो-ऑन-डिमाण्ड, मुफ्त गेम और 12 भाषाओं में ऑनलाइन शॉपिंग की सुविधा प्रदान करता है, जिसमें क्लासिक सामग्री का मिश्रण है।
- कंपनी US प्रीमियर लीग क्रिकेट और मन की बात जैसे कार्यक्रमों का प्रसारण करती है, तथा साइबर सुरक्षा जागरूकता के लिए CDAC के साथ सहयोग करती है।
- यह मंच एक परिवार-अनुकूल मंच है, जो भारत की सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करने वाली स्वच्छ, समावेशी सामग्री को बढ़ावा देता है।

केन्द्र सरकार 2025 में शुरू करेगी जनगणना

- केन्द्र सरकार ने वर्ष 2025 में जनगणना शुरू करने की योजना बनाई है, जिसे वर्ष 2026 तक पूरा करने का लक्ष्य है, तथा वर्ष 2028 तक लोकसभा सीटों का परिसीमन करने की घोषणा अक्टूबर, 2024 के अन्त में की गई है।
- जनगणना वर्ष 2025 में शुरू होगी, वर्ष 2026 में पूरी होगी, वर्ष 2026 के बाद सीमांकन होगा, वर्ष 2028 तक अपेक्षित होगा, तथा पारम्परिक दशकीय कार्यक्रम को तोड़ते हुए वर्ष 2035 तक समायोजित हो जाएगी।
- कांग्रेस के नेतृत्व में विपक्ष जाति आधारित जनगणना की वकालत कर रहा है, जिसमें सामान्य और SC-ST श्रेणियों के भीतर उप-सम्प्रदाय की विस्तृत जानकारी शामिल हो सकती है।
- मृत्युंजय कुमार नारायण (भारत के महारजिस्ट्रार और जनगणना आयुक्त) का कार्यकाल अगस्त, 2026 तक बढ़ाया गया, जिससे जनगणना नेतृत्व में निरन्तरता सुनिश्चित होगी।

कृषि नवाचार पर CII और ICRISAT का सहयोग

- भारतीय उद्योग परिसंघ (CII) तेलंगाना और अन्तर्राष्ट्रीय अर्ध-शुष्क उष्णकटिबन्धीय फसल अनुसंधान संस्थान (ICRISAT) सहयोग कर रहे हैं।
- इस सहयोग का उद्देश्य भारत में कृषि और खाद्य प्रसंस्करण नवाचार को बढ़ाना है। CII-तेलंगाना के अध्यक्ष साई प्रसाद ने ICRISAT को 15 नवम्बर, 2024 को CII के खाद्य और कृषि पैनल में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया।
- पैनल ने जलवायु परिवर्तन के प्रभाव, संसाधन प्रबन्धन के मुद्दे और बाजार पहुँच बाधाओं जैसे कृषि सम्बन्धी मुद्दों पर चर्चा की।
- CII-ICRISAT साझेदारी का उद्देश्य कृषि नवाचार को बढ़ाना, खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देना और कृषि जीवन में सुधार लाना है।
- ICRISAT का उद्देश्य जल की कमी, मृदा क्षरण और जलवायु लचीलेपन की समस्या का समाधान करके अर्ध-शुष्क क्षेत्रों में फसल की पैदावार को बढ़ाना है।

ऑपरेशन द्रोणागिरी का शुभारम्भ

- विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव प्रोफेसर अभय करदीकर ने 14 नवम्बर, 2024 को ऑपरेशन द्रोणागिरी का शुभारम्भ किया।
- ऑपरेशन द्रोणागिरी का लक्ष्य कॉर्पोरेट परिचालन और निवासियों के जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए भू-स्थानिक प्रौद्योगिकी के उपयोग को प्रदर्शित करना है।

- उत्तर प्रदेश, हरियाणा, असम, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में यह तीन मुख्य क्षेत्रों कृषि, आजीविका, तथा रसद एवं परिवहन पर ध्यान केन्द्रित करेगा।
- एकीकृत भू-स्थानिक डेटा विनिमय इण्टरफेस (GDI) परिष्कृत प्रोटोकॉल के माध्यम से गोपनीयता सुनिश्चित करता है।
- इससे पर्यावरण निगरानी, शहरी नियोजन और आपदा प्रबन्धन जैसे भौगोलिक डेटा तक आसान पहुँच और आदान-प्रदान की सुविधा मिलेगी।
- इस रणनीति का उद्देश्य भारत को भूस्थानिक प्रौद्योगिकी में वैश्विक नेता के रूप में स्थापित करना है।

CISF में पहली पूर्ण महिला बटालियन को मंजूरी

- केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) की पहली पूर्ण महिला इकाई को 12 नवम्बर, 2024 को मंजूरी दी गई।
- इसका उद्देश्य राष्ट्रीय सुरक्षा अभियानों में महिलाओं की जिम्मेदारी को मजबूत करना तथा उन्हें सशक्त बनाना है।
- वर्ष 1969 में CISF का गठन किया गया और यह हवाई अड्डों, मेट्रो रेल प्रणालियों, VIP सुरक्षा एवं महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे की सुरक्षा करता है।
- वर्तमान में, CISF बल में 7% से अधिक महिलाएँ हैं तथा यह अनुमान है कि महिला बटालियन के गठन से और अधिक महिलाओं को प्रेरणा मिलेगी।
- 53वें CISF दिवस समारोह के दौरान केन्द्रीय गृह मन्त्री अमित शाह के नेतृत्व में एक पूर्ण महिला बटालियन की अवधारणा सामने रखी गई।
- महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे की सुरक्षा करना और राष्ट्रीय सुरक्षा में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देना महिला बटालियन के लक्ष्यों में से एक है।
- यह कार्यक्रम देश के विकास में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी के लक्ष्य का समर्थन करता है।

NITI आयोग ने लॉन्च किया ASSET प्लेटफॉर्म

- विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मन्त्रालय तथा NITI आयोग ने 11 नवम्बर, 2024 को ASSET प्लेटफॉर्म (एक्सेलेरेटिंग सस्टेनेबल सॉल्यूशन फॉर एनर्जी ट्रांजिशन) की स्थापना की।
- यह राज्यों को ऊर्जा परिवर्तन योजनाएँ विकसित करने और परियोजनाएँ चलाने में सहायता करेगा, इसका मुख्य उद्देश्य भारत को हरित ऊर्जा की ओर तेजी से अग्रसर करना है।

- इसमें वर्ष 2047 तक विकसित देश (विकसित भारत) बनना और वर्ष 2070 तक शुद्ध-शून्य ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन तक पहुंचना शामिल है।
- NITI आयोग ने तीन प्रमुख कदम सुझाए हैं: ब्लूप्रिंट तैयार करना, परियोजना विकास, और नवीकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकियों में नवाचार को बढ़ावा देना।
- ऊर्जा दक्षता और ई-मोबिलिटी जैसे क्षेत्रों में, ASSET प्लेटफॉर्म अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी तथा सर्वोत्तम प्रथाओं पर प्रकाश डालेगा।
- इण्डियन सोसाइटी ऑफ इंजीनियरिंग जियोलॉजी (ISEG) फाउण्डेशन की भूमिका ज्ञान साझेदार के रूप में कार्य करके ऊर्जा संक्रमण को बढ़ावा देना है।

अन्तर-राज्यीय परिषद की नई स्थायी समिति

- प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 11 नवम्बर, 2024 को केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह को समिति का अध्यक्ष नियुक्त करने के लिए बदलावों को मंजूरी दी। समिति में केन्द्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, निर्मला सीतारमण आदि सहित 12 सदस्य शामिल हैं।
- इसका मुख्य उद्देश्य अन्तर-राज्यीय समन्वय और अन्य राज्यों के प्रति राज्य की कार्यवाहियों में प्रदर्शन को बढ़ाना है।
- अन्तर-राज्यीय परिषद इसके निर्णयों की देखरेख करेगी, तथा स्थायी समिति कार्यान्वयन की निगरानी करेगी।
- समिति विविध क्षेत्रीय सदस्यों को शामिल करते हुए संवाद आधारित दृष्टिकोण के माध्यम से जटिल केन्द्र राज्य सम्बन्धों का समाधान करती है।
- स्थायी समिति का उद्देश्य निर्णय लेने की दक्षता और समन्वय को बढ़ाना है, जिससे नीति कार्यान्वयन में सुधार हो सके।
- अन्तर-राज्यीय परिषद केन्द्र और राज्यों के बीच समन्वय स्थापित करती है, परामर्श के माध्यम से मुद्दों का समाधान करती है एवं विवादों का समाधान करती है।

विकेन्द्रीकृत हरित हाइड्रोजन पहल की शुरुआत

- भारत ने आवासीय और वाणिज्यिक अनुप्रयोगों के लिए हरित हाइड्रोजन उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए 10 नवम्बर, 2024 को ₹200 करोड़ की योजना शुरू की।
- इस योजना के अन्तर्गत फ्लोटिंग सोलर हाइड्रोजन उत्पादन, बायोमास हाइड्रोजन उत्पादन आदि जैसे नवीन समाधानों की खोज की जाएगी।

- यह योजना हरित हाइड्रोजन के विकेन्द्रीकृत अनुप्रयोगों को प्राथमिकता देती है, जैसे खाना पकाना, हिटिंग, ऑफ-ग्रिड विद्युत उत्पादन आदि।
- अमेरिकी बाजार की माँग और अडानी, वारी और विक्रम जैसी कंपनियों के योगदान से भारत का सौर पीवी निर्यात वर्ष 2023-24 में 230 गुना बढ़कर \$2 बिलियन हो गया।
- दक्षिण-पूर्व एशियाई आयातों पर टैरिफ सहित अमेरिकी व्यापार नीति में परिवर्तन से भारतीय सौर निर्यातकों को लाभ हो सकता है।
- भारत की बैटरी की माँग काफी हद तक आयात पर निर्भर है, अनुमान है कि वर्ष 2030 तक 70% बैटरी का आयात किया जाएगा।

सहारनपुर, रीवा और अम्बिकापुर हवाई अड्डों का उद्घाटन

- प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 20 अक्टूबर, 2024 को RCS-UDAN के अन्तर्गत रीवा, अम्बिकापुर और सहारनपुर हवाई अड्डों का उद्घाटन किया।
- RCS-UDAN योजना वर्ष 2016 में शुरू की गई थी, जिसका उद्देश्य क्षेत्रीय हवाई सम्पर्क को बढ़ावा देना है।
- इसकी पहली उड़ान शिमला से दिल्ली तक थी, जिसका उद्घाटन अप्रैल, 2017 में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने किया था।
- RCS-UDAN के अन्तर्गत 1.44 करोड़ से अधिक यात्रियों ने यात्रा की है, तथा 34 राज्यों/केन्द्रशासित प्रदेशों में 601 मार्ग और 86 हवाई अड्डे चालू हैं।
- UDAN 1.0 (2017) में अप्रयुक्त मार्गों पर ध्यान केन्द्रित किया गया था, UDAN 3.0 (2018) में जल हवाई अड्डों पर ध्यान केन्द्रित किया गया था तथा UDAN 5.1 (2023) में पहाड़ी क्षेत्रों में कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए हेलीकॉप्टर सेवाओं पर ध्यान केन्द्रित किया गया था।
- यह योजना खजुराहो, देवघर, अमृतसर, पासीघाट और अगत्ती द्वीप जैसे पर्यटन केन्द्रों के बीच कनेक्टिविटी में सुधार कर रही है।

डिजिटल जीवन प्रमाण-पत्र अभियान 3.0 का शुभारम्भ

डिजिटल जीवन प्रमाण-पत्र अभियान 3.0, 1-30 नवम्बर, 2024 तक चला और इसका उद्घाटन केन्द्रीय मंत्री जितेन्द्र सिंह ने किया। जीवन प्रमाण-पत्र या डिजिटल जीवन प्रमाण-पत्र एक इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्राप्त समाधान के आधार पर पेंशनभोगियों के जीवन को प्रमाणित करने वाला दस्तावेज है।

शुरुआत में इसे वर्ष 2014 में लॉन्च किया गया था, और फेस ऑथेंटिकेशन को वर्ष 2021 में शामिल किया गया था। पेंशनभोगियों के लिए DLC जमा करना पूरी तरह से सुविधाजनक है, क्योंकि वे इसे घर से या पेंशन वितरण बैंकों से भी भर सकते हैं। इसे 19 पेंशन संवितरण बैंकों, 57 पेंशन कल्याण संघों, रक्षा लेखा महानियंत्रक (CGDA) और UIDAI द्वारा समर्थित किया जाता है।



भारत ने शुरू की 21वीं पशुधन जनगणना

- डेटा-संचालित सतत विकास के उद्देश्य से जनगणना, रोग नियन्त्रण, नस्ल सुधार और ग्रामीण आजीविका पर ध्यान केन्द्रित करते हुए, केन्द्रीय मन्त्री ललन सिंह ने 25 अक्टूबर, 2024 को इसकी पहल की थी।
- 21वीं पशुधन गणना में 30 करोड़ से अधिक परिवारों को शामिल किया गया, जिसमें लिंग भूमिकाओं, नस्ल प्रबन्धन, पशु स्वास्थ्य और उत्पादकता पर ध्यान केन्द्रित किया गया।
- प्रौद्योगिकी में ऑफलाइन नस्ल पहचान के लिए मोबाइल ऐप-आधारित डेटा संग्रह, वेब-आधारित डैशबोर्ड के माध्यम से वास्तविक समय की निगरानी और 1 लाख से अधिक क्षेत्र कर्मियों का प्रशिक्षित कार्यबल शामिल है।
- यह जनगणना पशुधन, आजीविका में वृद्धि, कृषि सकल घरेलू उत्पाद, रोजगार और सतत विकास लक्ष्यों के साथ संरेखण के सम्बन्ध में आर्थिक अन्तर्दृष्टि प्रदान करती है।

‘हमसफर नीति’ का शुभारम्भ

- केन्द्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मन्त्री नितिन गडकरी ने 8 अक्टूबर, 2024 को नई दिल्ली में ‘हमसफर नीति’ का शुभारम्भ किया।
- इसका उद्देश्य राष्ट्रीय राजमार्गों पर यात्रा सुविधा में सुधार लाना तथा सड़क किनारे सुविधाओं के विकास को बढ़ावा देना है।
- नितिन गडकरी ने इस बात पर बल दिया कि इस पहल से स्थानीय हाशिए पर पड़े समुदायों को लाभ होगा तथा सुरक्षित और सुखद यात्रा सुनिश्चित करके समग्र यात्रा अनुभव में वृद्धि होगी।
- उन्होंने कहा कि नीति में पर्यावरणीय पहलुओं को प्राथमिकता दी गई है तथा इसमें जल एवं मृदा संरक्षण, अपशिष्ट पुनर्चक्रण तथा सौर ऊर्जा जैसे तत्वों को शामिल किया गया है।

खाद्य तेल और तिलहन पर राष्ट्रीय मिशन की शुरुआत

- सरकार ने 4 अक्टूबर, 2024 को वर्ष 2024-25 से वर्ष 2030-31 की अवधि के लिए राष्ट्रीय खाद्य तेल और तिलहन मिशन (NMEO-तिलहन) शुरू किया है, जिसका बजट ₹ 10103 करोड़ है।
- इस पहल का उद्देश्य अगले 7 वर्षों में तिलहन उत्पादन में आत्मनिर्भरता हासिल करना है।
- केन्द्रीय मन्त्री अश्विनी वैष्णव ने घोषणा की कि मिशन से सरसों, मूंगफली, सोयाबीन, सूरजमुखी एवं तिल सहित आवश्यक तिलहन फसलों का उत्पादन बढ़ेगा।
- इससे कपास के बीज, चावल की भूसी और वृक्ष-जनित तेल जैसे द्वितीयक स्रोतों से संग्रहण और निष्कर्षण दक्षता में भी सुधार होगा।
- मिशन का लक्ष्य प्राथमिक तिलहन उत्पादन को वर्ष 2022-23 में 39 मिलियन मीट्रिक टन से बढ़ाकर वर्ष 2030-31 तक 69.7 मिलियन मीट्रिक टन करना है।

भारत इंटरनेशनल एनर्जी एफिशिएंसी हब में शामिल

- केन्द्रीय मन्त्रिमण्डल ने 4 अक्टूबर, 2024 को इंटरनेशनल एनर्जी एफिशिएंसी हब में शामिल होने के लिए भारत के आशय पत्र पर हस्ताक्षर करने को मंजूरी दे दी।
- यह निर्णय सतत विकास के प्रति भारत की प्रतिबद्धता तथा ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करने की उसकी प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है।
- इसका सदस्य बनकर भारत एक दीर्घकालिक भविष्य की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति कर रहा है, कम कार्बन अर्थव्यवस्था में परिवर्तन को सुगम बना रहा है तथा ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ा रहा है।
- केन्द्रीय सूचना एवं प्रसारण मन्त्री अश्विनी वैष्णव ने इस बात पर प्रकाश डाला कि भारत को नवीन ऊर्जा प्रथाओं को साझा करने वाले 16 देशों के रणनीतिक समूह तक पहुंच प्राप्त होगी।
- सदस्यता से भारत को अन्य देशों के साथ सहयोग करने, अपनी विशेषज्ञता साझा करने तथा वैश्विक जलवायु परिवर्तन प्रयासों में योगदान करते हुए अन्तर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाने में मदद मिलेगी।

'अन्न दर्पण' पहल का शुभारम्भ

- भारतीय खाद्य निगम (FCI) ने 3 अक्टूबर, 2024 को अपने 100 दिवसीय उपलब्धि कार्यक्रम के हिस्से के रूप में 'ANNA DARPAN' नामक एक महत्वपूर्ण डिजिटल परिवर्तन पहल की घोषणा की।

- यह नया डिजिटल प्लेटफॉर्म पुरानी डिपो ऑनलाइन प्रणाली का स्थान लेगा और मण्डियों, मिलों एवं डिपो सहित खाद्य आपूर्ति शृंखलाओं के प्रबन्धन को बढ़ाएगा।
- अन्न दर्पण का उद्देश्य दक्षता और उत्पादकता में सुधार करना, उपयोगकर्ता के अनुकूल इंटरफेस प्रदान करना, सूचित निर्णय लेने के लिए डेटा एनालिटिक्स का उपयोग करना, अन्य प्रणालियों के साथ एकीकरण करना, दोहराव को समाप्त करने के लिए वर्तमान प्लेटफॉर्मों को समेकित करना एवं चलते-फिरते उपयोगकर्ताओं के लिए मोबाइल पहुंच का समर्थन करना है।
- कोफोर्ड लिमिटेड को इस क्लाउड-आधारित प्लेटफॉर्म को डिजाइन करने, विकसित करने और रखरखाव करने के लिए चुना गया है, ताकि विभिन्न सिस्टम घटकों में प्रभावी संचार सुनिश्चित हो सके।

पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 'क्रूज भारत मिशन' का शुभारम्भ

- केन्द्रीय बन्दरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मन्त्री सर्बानंद सोनोवाल ने 1 अक्टूबर, 2024 को मुम्बई बन्दरगाह पर 'क्रूज भारत मिशन' का शुभारम्भ किया।
- इस पहल का उद्देश्य वर्ष 2029 तक क्रूज यात्रियों की संख्या को दोगुना करके भारत को वैश्विक क्रूज पर्यटन केन्द्र के रूप में स्थापित करना है।
- यह मिशन 3 क्रूज खण्डों पर ध्यान केन्द्रित करेगा—महासागर और बन्दरगाह, नदी एवं अन्तर्देशीय, और द्वीप खण्ड। इसे 3 चरणों में लागू किया जाएगा :
- 1. चरण 1 (1 अक्टूबर, 2024-30 सितम्बर, 2025) : अध्ययन करना, मास्टर प्लानिंग करना और मौजूदा बुनियादी ढाँचे का आधुनिकीकरण करना।
- 2. चरण 2 (1 अक्टूबर, 2025-31 मार्च, 2027) : नए टर्मिनल और गंतव्य विकसित करना।
- 3. चरण 3 (1 अप्रैल, 2027-31 मार्च, 2029) : क्रूज सर्किटों को एकीकृत करना और बुनियादी ढाँचे में निरन्तर सुधार करना।

भारत बना तीसरा सबसे बड़ा इथेनॉल उत्पादक और उपभोक्ता

- जैव ईंधन को बढ़ावा देने और ऊर्जा स्थिरता को बढ़ाने के उद्देश्य से किए गए महत्वपूर्ण नीतिगत सुधारों से प्रेरित होकर, भारत 30 सितम्बर, 2024 को वैश्विक स्तर पर इथेनॉल का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता बनकर उभरा।

- सरकार ने इथेनॉल उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न कार्यक्रम शुरू किए हैं, जिसमें गन्ना किसानों और उत्पादकों को वित्तीय सहायता प्रदान करना भी शामिल है।
- ये पहल ईंधन मिश्रण के लिए इथेनॉल की उपलब्धता बढ़ाने, जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करने तथा ग्रामीण किसानों को समर्थन देने के लिए डिजाइन की गयी है।
- भारतीय चीनी एवं जैव ऊर्जा निर्माता संघ द्वारा सितम्बर, 2024 में आयोजित भारत चीनी एवं जैव ऊर्जा सम्मेलन में नीति निर्माताओं और उद्योग जगत के नेताओं को इन क्षेत्रों के भविष्य पर चर्चा करने के लिए एक साथ लाया गया।
- इस वर्ष का विषय 'सुगम स्थिरता का सामंजस्य: हरित अर्थव्यवस्था के लिए भारत के पथ को आगे बढ़ाना' था।
- यह चीनी और जैव-ऊर्जा उद्योगों में पर्यावरण-अनुकूल समाधानों को आगे बढ़ाने के लिए दीर्घकालिक प्रथाओं एवं सहयोग पर बल देता है।

BRAP 2024 पहल की घोषणा

- वाणिज्य और उद्योग मन्त्रालय ने 30 सितम्बर, 2024 को मेक इन इण्डिया पहल को बढ़ावा देने के लिए 'व्यापार सुधार कार्य योजना' (BRAP) 2024 शुरू करने की घोषणा की।
- मन्त्रालय ने कहा कि BRAP का उद्देश्य सम्पूर्ण देश में व्यवसायों के लिए एक निर्बाध नियामक ढाँचा तैयार करना है, जिससे व्यापार करने में सरलता हो।
- यह पहल प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करेगी, अनुपालन बोझ को कम करेगी, तथा डिजिटल समाधानों को शामिल करके भारत को वैश्विक निवेश के लिए पसंदीदा गंतव्य के रूप में स्थापित करेगी।
- इसके अतिरिक्त, BRAP एक नवीन मूल्यांकन पद्धति को क्रियान्वित करेगा, जो अधिक गहन और अनुकूलनीय दृष्टिकोण के लिए साक्ष्य-आधारित एवं फीडबैक-आधारित मूल्यांकन को संयोजित करेगा।

मनाया गया 7वाँ राष्ट्रीय पोषण माह

- सम्पूर्ण भारत में 27 सितम्बर, 2024 को मनाया गया 7वाँ राष्ट्रीय पोषण माह, कुपोषण के विरुद्ध देश की लड़ाई में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि साबित हुआ।
- सम्पूर्ण माह चलने वाला यह अभियान भारत के पोषण सम्बन्धी कमियों को दूर करने के मिशन के लिए महत्वपूर्ण है और इसने स्वास्थ्य एवं पोषण के बारे में चर्चा को पुनर्जीवित कर दिया है।
- इस वर्ष के अभियान में एनीमिया मुक्त भारत पहल पर बल दिया गया है, जिसमें 6x6x6

रणनीति का उपयोग किया गया है, जो 6 संस्थानों में 6 हस्तक्षेपों के माध्यम से 6 आयु समूहों को लक्षित करता है।

- अगस्त, 2024 तक, इस रणनीति के सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं, 95% गर्भवती महिलाओं और 65.9% स्तनपान कराने वाली महिलाओं को 180 आयरन और फोलिक एसिड (IFA) की गोलीयाँ दी गई हैं, जिससे मातृ और बाल स्वास्थ्य परिणामों में काफी सुधार हुआ है।

‘पर्यटन मित्र’ और ‘पर्यटन दीदी’ पहल का शुभारम्भ

- पर्यटन मन्त्रालय ने 27 सितम्बर, 2024 को ‘पर्यटन मित्र’ और ‘पर्यटन दीदी’ नामक एक राष्ट्रीय जिम्मेदार पर्यटन पहल शुरू की।
- इस पहल का उद्देश्य आगंतुकों को ‘पर्यटक-मित्रवत’ व्यक्तियों से जोड़कर पर्यटक अनुभव को बढ़ाना है, जो अपने गंतव्य के लिए गौरवशाली राजदूत और कहानीकार के रूप में कार्य करते हैं।
- प्रत्येक स्थान की विशिष्ट क्षमता के अनुरूप हेरिटेज वॉक, फूड टूर, शिल्प पर्यटन, प्रकृति ट्रेक और होमस्टे सहित नई पर्यटन पेशकशों को विकसित करने के लिए महिलाओं एवं युवाओं को प्रशिक्षित करने पर महत्वपूर्ण ध्यान दिया गया है।
- प्रशिक्षण में पर्यटन-विशिष्ट अनुदेश के साथ-साथ डिजिटल साक्षरता और उपकरणों का सामान्य प्रशिक्षण भी शामिल है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ये अनुभव वैश्विक स्तर पर पर्यटकों के लिए दृश्यमान और सुलभ हों।

सरकार द्वारा न्यूनतम मजदूरी दर में वृद्धि

- केन्द्र सरकार ने 26 सितम्बर, 2024 को परिवर्तनीय महंगाई भत्ते में संशोधन किया है, जिसके परिणामस्वरूप न्यूनतम मजदूरी दरों में वृद्धि हुई।
- नई दरें 1 अक्टूबर से प्रभावी होंगी और इन्हें कौशल स्तरों – अकुशल, अर्ध-कुशल, कुशल और उच्च कुशल – के साथ-साथ भौगोलिक वर्गीकरण A, B और C के आधार पर विभाजित किया गया।
- क्षेत्र ‘A’ में निर्माण, झाड़ू लगाने, सफाई, लोडिंग-अनलोडिंग जैसे क्षेत्रों में अकुशल श्रमिकों को अब ₹ 783 प्रतिदिन मिलेगा।
- अर्ध-कुशल श्रमिकों को प्रतिदिन ₹ 868 मिलेगा, जबकि कुशल, लिपिक, तथा निगरानी एवं रखवाली (बिना हथियार वाले) श्रमिकों को प्रतिदिन ₹ 954 मिलेगा।
- अत्यधिक कुशल श्रमिकों और निगरानी एवं रखवाली (हथियार सहित) कार्मिकों को न्यूनतम वेतन ₹ 1035 प्रतिदिन मिलेगा।

- ये परिवर्तन विभिन्न क्षेत्रों में श्रमिकों के वेतन में सुधार के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं।

ग्लोबल इनोवेशन इण्डेक्स 2024 में भारत का 39वाँ स्थान

- भारत 26 सितम्बर, 2024 को ग्लोबल इनोवेशन इण्डेक्स (GII) 2024 में 133 वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं में 39वें स्थान पर पहुँच गया।



- केन्द्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मन्त्री पीयूष गोयल ने घोषणा की कि मध्य एवं दक्षिणी एशिया क्षेत्र की 10 अर्थव्यवस्थाओं में भारत पहले स्थान पर है।
- इसके अतिरिक्त, भारत निम्न-मध्यम आय वाली अर्थव्यवस्थाओं में प्रथम स्थान पर है तथा वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रोपर्टी ऑर्गेनाइजेशन (WIPO), साइंस एण्ड टेक्नोलॉजी (S&T) क्लस्टर रैंकिंग में चौथे स्थान पर है।
- मुम्बई, दिल्ली, बेंगलुरु और चेन्नई जैसे प्रमुख भारतीय शहर विश्व के शीर्ष 100 साइंस एण्ड टेक्नोलॉजी क्लस्टर में शामिल हैं, और भारत इन्टैन्जबल एसेट इंटेसिटी में विश्व स्तर पर सातवें स्थान पर है।
- वर्ष 2015 में 81वें स्थान पर आने के बाद से GII में यह भारत का सुधार महत्वपूर्ण है, जिसमें स्विट्जरलैण्ड, स्वीडन, अमेरिका, सिंगापुर और ब्रिटेन को सबसे नवीन अर्थव्यवस्थाओं के रूप में मान्यता दी गई।

मेक इन इण्डिया के 10 वर्ष पूर्ण

- मेक इन इण्डिया पहल ने 25 सितम्बर, 2024 को अपनी 10वीं वर्षगांठ मनाई, जिसने भारत के विनिर्माण क्षेत्र और आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण प्रगति को प्रदर्शित किया।
- निवेश आकर्षित करने और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2014 में शुरू की गई इस योजना ने भारत को एक विनिर्माण केन्द्र में बदल दिया है।
- यह पहल अन्तरिक्ष, अर्धचालक और इलेक्ट्रिक वाहनों जैसे विविध क्षेत्रों में फैली हुई है, जिससे भारत दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल उत्पादक बन गया है और आयात में 85% की कमी आई है।
- उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना ने ₹ 1.28 लाख करोड़ का निवेश आकर्षित किया। भारत ने

प्रत्येक घण्टे एक स्टार्टअप शुरू किया है, जिससे 1.5 मिलियन नौकरियाँ उत्पन्न हुई हैं।

- प्रमुख उपलब्धियों में COVID-19 वैक्सीन उत्पादन में वैश्विक नेतृत्व, वन्दे भारत ट्रेन और UPI के माध्यम से डिजिटल भुगतान में प्रभुत्व शामिल हैं।

वर्ल्ड फूड इण्डिया 2024 का समापन

- चार दिवसीय मेगा इवेंट, वर्ल्ड फूड इण्डिया 2024, 19 सितम्बर को नई दिल्ली के भारत मण्डप में शुरू होने के बाद 22 सितम्बर, 2024 को सम्पन्न हुआ।
- लगभग 90 देशों, 26 राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों तथा 18 केन्द्रीय मन्त्रालयों ने इसमें भाग लिया, जिससे खाद्य प्रसंस्करण में भारत के बढ़ते प्रभाव का प्रदर्शन हुआ।
- इस तीसरे संस्करण में 40 से अधिक ज्ञान सत्र शामिल थे, जिनमें विषयगत चर्चाएँ और राज्य-विशिष्ट सम्मेलन शामिल थे।
- इसमें जापान साझेदार देश था, जबकि वियतनाम और ईरान पर विशेष ध्यान दिया गया था।
- इस कार्यक्रम के दौरान भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण द्वारा आयोजित ग्लोब
- ल फूड रेगुलेटर्स समिट भी आयोजित हुआ।

भारत करेगा वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एण्ड एन्टरटेनमेन्ट समिट 2025 की मेजबानी

- भारत पहली बार 5 से 9 फरवरी, 2025 तक वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एण्ड एन्टरटेनमेन्ट समिट (WAVES) की मेजबानी करेगा, जैसा कि 21 सितम्बर, 2024 को घोषणा की गई।
- इस शिखर सम्मेलन का उद्देश्य भारत के मीडिया और मनोरंजन उद्योग को बढ़ावा देना तथा इसकी वैश्विक उपस्थिति को बढ़ाना है।
- इसमें मीडिया और मनोरंजन के सम्पूर्ण क्षेत्र को शामिल किया जाएगा तथा उद्योग जगत के नेताओं के बीच संवाद, नवाचार और व्यापार साझेदारी को प्रोत्साहित किया जाएगा।
- मुख्य चर्चाओं में प्रवृत्तियों, चुनौतियों और अवसरों पर चर्चा की जाएगी, विशेष रूप से इस क्षेत्र में परिवर्तन लाने वाली नई प्रौद्योगिकियों के सन्दर्भ में।
- एनीमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक्स (AVGC) क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा, जो तेजी से वैश्विक मान्यता प्राप्त कर रहे हैं।
- प्रसार भारती की ‘बैटल ऑफ द बैण्ड्स’ और ‘सिम्फनी ऑफ इण्डिया’ सहित कई प्रतियोगिताओं में शिखर सम्मेलन से पहले सम्पूर्ण देश के रचनाकारों को शामिल किया जाएगा।

श्वेत क्रान्ति 2.0 की शुरुआत

- केन्द्रीय मन्त्री अमित शाह ने 21 सितम्बर, 2024 को ऑपरेशन फ्लड की सफलता के आधार पर भारत के डेयरी क्षेत्र को बढ़ाने के लिए 'श्वेत क्रान्ति 2.0' की घोषणा की।
- वर्ष 1970 में शुरू की गई इस योजना ने सहकारी समितियों के माध्यम से उद्योग को बदल दिया और भारत एक को अग्रणी दूध उत्पादक बना दिया।
- श्वेत क्रान्ति 2.0 का मुख्य उद्देश्य अगले पाँच वर्षों में दूध संग्रह में 50% की वृद्धि करना है।
- इसका लक्ष्य वर्ष 2028-29 तक दैनिक खरीद को 660 लाख किग्रा से बढ़ाकर 1007 लाख किग्रा करना है।
- यह पहल सहकारी नेटवर्क का विस्तार करके डेयरी किसानों के लिए बाजार पहुँच में सुधार करेगी, जिसमें वर्तमान में लगभग 1.7 लाख समितियाँ शामिल हैं, जो 30% गाँवों को कवर करती हैं और राष्ट्रीय दूध उत्पादन का 10% सम्भालती हैं।

'वन नेशन, वन इलेक्शन'

प्रस्ताव को मंजूरी

- केन्द्रीय मन्त्रिमण्डल ने 19 सितम्बर, 2024 को पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्द की अध्यक्षता में एक साथ चुनाव (वन नेशन, वन इलेक्शन-ONOE) कराने की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया।
- इस प्रस्ताव का उद्देश्य राज्य और लोकसभा चुनावों को एक साथ कराना है, जिससे मतदाता एक ही दिन दोनों चुनावों के लिए वोट डाल सकें।
- सितम्बर, 2023 में गठित समिति ने मार्च, 2024 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। जिसके अनुसार वर्ष 1951 से 1967 के बीच एक साथ चुनाव सम्पन्न हुए हैं।
- पिछली रिपोर्टों, जैसे विधि आयोग की 170वीं (1999) और संसदीय समिति की 79वीं (2015), में भी इसी प्रकार के विचारों पर विचार किया गया था।
- रामनाथ कोविन्द के नेतृत्व वाली समिति ने राजनीतिक दलों और विशेषज्ञों से परामर्श किया और देश में एक साथ चुनाव कराने की अवधारणा के लिए व्यापक समर्थन पाया।

भारत जल सप्ताह 2024 आयोजित

- भारत मण्डपम, प्रगति मैदान, नई दिल्ली में 17 सितम्बर, 2024 को 'भारत जल सप्ताह 2024' शुरू हुआ।
- वर्ष 2024 का विषय 'समावेशी जल विकास और प्रबन्धन के लिए साझेदारी और सहयोग' था।

- इस कार्यक्रम में एक बहु-विषयक सम्मेलन और एक प्रदर्शनी शामिल हुई, जिसमें सम्पूर्ण विश्व से 3000 से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया।
- इसमें जल सुरक्षा, एकीकृत प्रबन्धन और शासन पर विषयगत सत्र आयोजित किये गये।
- इस सम्मेलन का उद्देश्य जल चुनौतियों से निपटने, सतत प्रथाओं को बढ़ावा देने और समान जल वितरण के लिए संसाधन आवण्टन को बढ़ाने के लिए हितधारकों के मध्य सहयोग को बढ़ावा देना था, ताकि भारत में जल प्रबन्धन के लिए एक लचीला भविष्य सुनिश्चित हो सके।

मिशन मौसम पहल को मंजूरी

- केन्द्रीय मन्त्रिमण्डल द्वारा 13 सितम्बर, 2024 को मंजूर की गई मिशन मौसम पहल का उद्देश्य 2 वर्षों (2024-26) में ₹ 2000 करोड़ के बजट के साथ मौसम पूर्वानुमान और जलवायु विज्ञान क्षमताओं को बढ़ाना है।
- यह पहल विभिन्न भौगोलिक और लौकिक पैमानों पर मौसम सम्बन्धी पूर्वानुमानों की सटीकता एवं समयबद्धता में सुधार करने के लिए अगली पीढ़ी के रेडार, उपग्रहों तथा उच्च प्रदर्शन कंप्यूटिंग प्रणालियों को तैनात करने पर केन्द्रित है।
- मिशन मौसम से कृषि, आपदा प्रबन्धन, विमानन और स्वास्थ्य सहित कई क्षेत्रों को सीधे लाभ होगा, क्योंकि इससे समय पर मौसम सम्बन्धी जानकारी मिलेगी एवं चरम मौसम की घटनाओं तथा जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के विरुद्ध सामुदायिक लचीलापन बढ़ेगा।

संसदीय कार्य मन्त्रालय की 6 पहलों का शुभारम्भ

- संसदीय कार्य मन्त्री किरन रिजिजू ने 11 सितम्बर, 2024 को नई दिल्ली में मन्त्रालय की 100 दिवसीय उपलब्धियों के हिस्से के रूप में 6 नई पहलों का उद्घाटन किया।
- उन्होंने निम्नलिखित 6 पहलों का उद्घाटन किया:-

- राष्ट्रीय ई-विधान एप्लीकेशन 2.0 (NeVA 2.0)
- अधीनस्थ विधान प्रबन्धन प्रणाली
- परामर्शदात्री समिति प्रबन्धन प्रणाली
- राष्ट्रीय युवा संसद योजना 2.0
- एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय (EMRSs)
- NeVA मोबाइल ऐप संस्करण 2.0

- उन्नत यूजर इंटरफेस और राज्य विधानसभाओं के साथ बेहतर एकीकरण के साथ, इसका उद्देश्य कागज रहित विधायी वातावरण बनाना और अधिक कुशल निर्णय लेने के लिए वास्तविक समय शासन को बढ़ाना है।

जल्द ही शुरू होगी 'INDIAsize' पहल

- सरकार भारतीय शरीर के प्रकारों के अनुकूल मानकीकृत शारीरिक माप स्थापित करने के लिए 'INDIAsize' पहल शुरू करने के लिए तैयार है।
- वर्तमान में, भारत में अन्तर्राष्ट्रीय और घरेलू ब्राण्ड US और UK के आकार मानकों पर निर्भर हैं, जो 'छोटे', 'मध्यम' और 'बड़े' आकार की पेशकश करते हैं।
- हालाँकि, भारतीय शरीर के प्रकार ऊँचाई, भार और शरीर के विशिष्ट माप के विषय में पश्चिमी लोगों से भिन्न होते हैं, जिसके कारण अक्सर फिटिंग सम्बन्धी समस्याएँ उत्पन्न होती हैं।
- वस्त्र मन्त्रालय ने भारतीय परिधान उद्योग के लिए मानक शरीर आकार स्थापित करने हेतु INDIAsize परियोजना को मंजूरी दी है, जिसका उद्देश्य कपड़ों के फिट में असमानताओं और असंगतियों को हल करना है।

कैबिनेट द्वारा मिशन मौसम को मंजूरी

- प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मन्त्रिमण्डल ने 11 सितम्बर, 2024 को दो वर्षों के लिए ₹ 2000 करोड़ के परिव्यय के साथ 'मिशन मौसम' को मंजूरी दी।
- मिशन मौसम, जिसे मुख्य रूप से पृथ्वी विज्ञान मन्त्रालय द्वारा क्रियान्वित किया जाएगा, को भारत के मौसम और जलवायु से सम्बन्धित विज्ञान, अनुसंधान और सेवाओं को जबरदस्त बढ़ावा देने के लिए एक बहुआयामी और परिवर्तनकारी पहल माना जाता है।
- मिशन का फोकस समय और स्थान के पैमाने पर अत्यधिक सटीक और समय पर मौसम और जलवायु की जानकारी प्रदान करने के लिए अवलोकन और समझ में सुधार करना होगा, जिसमें मानसून पूर्वानुमान, वायु गुणवत्ता के लिए अलर्ट, चरम मौसम की घटनाएँ और चक्रवात, कोहरे, ओलावृष्टि और बारिश आदि के प्रबंधन के लिए मौसम हस्तक्षेप, क्षमता निर्माण और जागरूकता पैदा करना शामिल है।
- मिशन मौसम से कृषि, आपदा प्रबन्धन, रक्षा, पर्यावरण, विमानन, जल संसाधन, बिजली, पर्यटन, शिपिंग, परिवहन, ऊर्जा और स्वास्थ्य जैसे कई क्षेत्रों को सीधे लाभ होगा।
- यह शहरी नियोजन, सड़क और रेल परिवहन, अपतटीय परिचालन और पर्यावरण निगरानी जैसे क्षेत्रों में डेटा-संचालित निर्णय लेने को भी बढ़ावा देगा।

23वाँ विधि आयोग गठित

- केन्द्र सरकार द्वारा 2 सितम्बर, 2024 को 23वें विधि आयोग के गठन की अधिसूचना जारी की गई।

- आयोग का कार्यकाल 31 अगस्त, 2027 तक तीन वर्ष की अवधि के लिए होगा। आयोग में निम्नलिखित शामिल होंगे
- एक पूर्णकालिक अध्यक्ष
- चार पूर्णकालिक सदस्य (सदस्य-सचिव सहित)
- सचिव, विधि मामलों के विभाग पदेन सदस्य
- सचिव, विधायी विभाग पदेन सदस्य
- पांच से अधिक अंशकालिक सदस्य नहीं
- विधि आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में होगा।

सर्वोच्च न्यायालय के नए ध्वज और प्रतीक चिह्न का अनावरण

- राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 3 सितम्बर, 2024 को नई दिल्ली में जिला न्यायापालिका के राष्ट्रीय सम्मेलन में भारत के सर्वोच्च न्यायालय का नया ध्वज और प्रतीक चिह्न प्रस्तुत किया।
- ध्वज, जो मुख्य रूप से नीला है, विश्वास, ज्ञान और न्याय का प्रतिनिधित्व करता है, और इसमें महत्वपूर्ण प्रतीक हैं: अशोक चक्र, जो कानून के शाश्वत चक्र को दर्शाता है; सर्वोच्च न्यायालय भवन, जो न्यायिक अधिकार को दर्शाता है; भारत का संविधान, जो राष्ट्र की कानूनी प्रणाली की नींव को दर्शाता है। ये प्रतीक संविधान और न्याय के रक्षक के रूप में सर्वोच्च न्यायालय की भूमिका को रेखांकित करते हैं।
- नए प्रतीक चिह्न में देवनागरी लिपि में 'यतो धर्मस्ततो जयः' वाक्यांश शामिल है, जिसका अर्थ है 'जहाँ धर्म है, वहाँ विजय है'। यह संस्कृत अभिव्यक्ति न्यायालय के निर्णयों में न्याय और धार्मिकता के प्रति समर्पण को उजागर करती है।

सर्वोच्च न्यायालय के 75 वर्ष पूरे होने पर स्मारक डाक टिकट

- प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 2 सितम्बर, 2024 को भारत मण्डपम, नई दिल्ली में जिला न्यायाधीशों के सम्मेलन के दौरान भारत के सर्वोच्च न्यायालय के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में एक स्मारक डाक टिकट जारी किया।
- यह डाक टिकट 28 जनवरी, 190 को अपनी स्थापना के बाद से सर्वोच्च न्यायालय की महत्वपूर्ण भूमिका का जश्न मनाता है।
- यह कानून के शासन को कायम रखने, नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करने तथा सम्पूर्ण भारत में न्याय प्रदान करने में न्यायालय के योगदान पर प्रकाश डालता है।
- यह टिकट सर्वोच्च न्यायालय की चिरस्थायी विरासत का सम्मान करता है और देश के न्यायिक इतिहास में इसकी महत्वपूर्ण उपलब्धि को रेखांकित करता है, जो पिछले 75 वर्षों में न्याय और कानूनी अखण्डता के प्रति इसकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

खाद्य पदार्थों में माइक्रोप्लास्टिक संदूषण से निपटने हेतु परियोजना

- भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने 18 अगस्त, 2024 को खाद्य पदार्थों में माइक्रोप्लास्टिक संदूषण की समस्या के समाधान के लिए नई दिल्ली में एक नई परियोजना का शुभारम्भ किया।
- इस परियोजना का उद्देश्य खाद्य उत्पादों में सूक्ष्म और नैनोप्लास्टिक का पता लगाने के लिए तरीकों को विकसित और मान्य करना है।
- प्राथमिक लक्ष्यों में सूक्ष्म और नैनोप्लास्टिक्स के विश्लेषण करने के लिए मानक प्रोटोकॉल बनाना, विभिन्न प्रयोगशालाओं के मध्य तुलना करना और माइक्रोप्लास्टिक्स के प्रति उपभोक्ता के सम्पर्क पर महत्वपूर्ण डेटा एकत्र करना शामिल है।

अपंजीकृत नम्बरों से वॉयस प्रमोशनल कॉल पर प्रतिबन्ध

- भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (TRAI) ने 14 अगस्त, 2024 को सभी एक्सेस सेवा प्रदाताओं को अपंजीकृत टेलीमार्केटर्स से वॉयस प्रमोशनल कॉल पर तुरंत प्रतिबंध का आदेश दिया।
- संचार मन्त्रालय के अनुसार, यदि कोई अपंजीकृत प्रेषक वाणिज्यिक कॉल के लिए दूरसंचार संसाधनों का उपयोग करते हुए पाया जाता है, तो उसे मूल पहुँच प्रदाता द्वारा 2 वर्ष तक के लिए ब्लैकलिस्ट में डाल दिया जाएगा, जिसके दौरान उसे कोई नया दूरसंचार संसाधन उपलब्ध नहीं कराया जाएगा।
- इसके अतिरिक्त, सभी अपंजीकृत प्रेषकों को एक माह के भीतर वितरित खाता प्रौद्योगिकी (DLT) प्लेटफॉर्म पर स्थानान्तरित होना होगा।

BIS स्थापित करेगा मानकीकरण विभाग

- भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) ने 9 अगस्त, 2024 को आयुष प्रथाओं के मानकीकरण के लिए समर्पित एक नए विभाग के निर्माण की घोषणा की।

'डिजिटल शक्ति केन्द्र' का शुभारम्भ

- नई दिल्ली में 5 अगस्त, 2024 को महिला आयोग (NCW) ने महिलाओं के विरुद्ध साइबर अपराधों से निपटने के लिए डिजिटल शक्ति केन्द्र का शुभारम्भ किया।
- इस सुविधा का उद्देश्य जागरूकता बढ़ाना तथा साइबर अपराध की शिकायतों को दर्ज करना और उनका समाधान करने के लिए तकनीकी सहायता प्रदान करना है।
- यह पहल पहचान की चोरी, साइबरस्टॉकिंग और यौन शोषण जैसे बढ़ते साइबर अपराधों से निपटने के लिए शुरू की गई है। वर्ष 2018 के डिजिटल शक्ति अभियान की सफलता के आधार पर, केन्द्र समय पर और प्रभावी शिकायत समाधान के लिए विशेषज्ञ मार्गदर्शन प्रदान करेगा।

- उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मन्त्रालय द्वारा शुरू की गई इस पहल का उद्देश्य आयुष उत्पादों की सुरक्षा, प्रभावशीलता और गुणवत्ता में सुधार करना है।
- विभाग में आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध, सोबा-रिग्पा और होम्योपैथी शामिल होंगे।
- BIS के महानिदेशक प्रमोद कुमार के अनुसार नया आयुष विभाग 7 अनुभागीय समितियों की स्थापना करेगा, जिनमें से प्रत्येक एक विशिष्ट आयुष प्रणाली की देखरेख करती है।
- ये समितियाँ हितधारकों के साथ मिलकर साक्ष्य-आधारित मानक तैयार करेंगी, जो राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय दोनों दिशा-निर्देशों के अनुरूप होंगे।

राष्ट्रपति भवन के 'दरबार हॉल' और 'अशोक हॉल' के नाम परिवर्तित

- राष्ट्रपति भवन में 25 जुलाई, 2024 को 'दरबार हॉल' का नाम बदलकर 'गणतन्त्र मण्डप' और अशोक हॉल का नाम बदलकर 'अशोक मण्डप' कर दिया गया।
- राष्ट्रपति सचिवालय ने घोषणा की कि इन परिवर्तनों का उद्देश्य आयोजन स्थल को भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों के प्रति अधिक प्रतिबिम्बित करना है।
- दरबार हॉल, जिसका नाम पहले भारतीय शासकों और अंग्रेजों के अधीन न्यायालयों के लिए उपयोग किए जाने वाले शब्द के आधार पर रखा गया था, का नाम बदलकर 'गणतन्त्र मण्डप' कर दिया गया है, जो भारतीय गणतन्त्र की अवधारणा के अनुरूप है।
- यह नया नाम भारत के गहरे गणतान्त्रिक मूल्यों को दर्शाता है। अशोक हॉल, जो मूल रूप से एक बॉलरूम था, का नाम बदलकर 'अशोक मण्डप' कर दिया गया।
- अशोक शब्द का अर्थ 'सभी दुखों से मुक्त' है, यह शब्द सम्राट अशोक को भी सन्दर्भित करता है, जो एकता और शान्ति का प्रतीक है।



भारत 'सप्लाई चेन काउन्सिल का उपाध्यक्ष' चयनित

- भारत को 31 जुलाई, 2024 को सप्लाई चेन काउन्सिल के उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया, जो राष्ट्र के लिए एक उल्लेखनीय उपलब्धि है।
- वाणिज्य एवं उद्योग मन्त्रालय ने भारत और 13 अन्य इण्डो-पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क (IPEF) साझेदारों द्वारा इण्डो-पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉसेपेरीटी समझौते के अन्तर्गत 3 आपूर्ति शृंखला निकायों की स्थापना पर प्रकाश डाला।
- संयुक्त राज्य अमेरिका आपूर्ति शृंखला परिषद् का अध्यक्ष है, जबकि कोरिया और जापान क्रमशः अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के रूप में संकट प्रतिक्रिया नेटवर्क का नेतृत्व करते हैं।
- संयुक्त राज्य अमेरिका श्रम अधिकार सलाहकार बोर्ड का भी अध्यक्ष है, जबकि फिजी इसका उपाध्यक्ष है।

भारत को 'एशियन डिजास्टर प्रीपेयर्डनेस सेण्टर' की अध्यक्षता

- भारत ने 25 जुलाई, 2024 को 'एशियन डिजास्टर प्रीपेयर्डनेस सेण्टर' (ADPC) की अध्यक्षता सम्भाली। ADPC एक स्वतन्त्र अन्तर्राष्ट्रीय संगठन है जो एशिया और प्रशान्त क्षेत्र में आपदा जोखिम न्यूनीकरण और जलवायु लचीलापन बढ़ाने पर केन्द्रित है।
- भारत, 8 पड़ोसी देशों-बांग्लादेश, कम्बोडिया, चीन, नेपाल, पाकिस्तान, फिलीपींस, श्रीलंका और थाईलैण्ड-के साथ ADPC का संस्थापक सदस्य है।
- भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करते हुए राजेंद्र सिंह ने बैंकॉक, थाईलैण्ड में एक समारोह के दौरान वर्ष 2024-25 के कार्यकाल के लिए चीन से अध्यक्ष पद ग्रहण किया।
- केन्द्रीय गृह मन्त्रालय ने प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में आपदा जोखिम न्यूनीकरण में भारत के बढ़ते वैश्विक और क्षेत्रीय नेतृत्व पर प्रकाश डाला तथा आपदा प्रतिरोधी अवसंरचना के लिए अन्तर्राष्ट्रीय गठबन्धन जैसी पहलों का उल्लेख किया।

NTIPRIT, NICF और WMTDC का विलय होकर बनी एक इकाई

- दूरसंचार विभाग ने 20 जुलाई, 2024 को 3 प्रशिक्षण संस्थानों को राष्ट्रीय संचार अकादमी (NCA) नामक एक नई इकाई में विलय कर दिया।
- ये संस्थान राष्ट्रीय दूरसंचार नीति अनुसन्धान, नवाचार और प्रशिक्षण संस्थान (NTIPRIT), राष्ट्रीय संचार वित्त संस्थान (NICF) और

तीन नए आपराधिक कानून हुए लागू

- भारतीय न्याय संहिता (BNS) 1 जुलाई, 2024 को भारत की आधिकारिक आपराधिक संहिता बन गई, दिसम्बर, 2023 में पारित होने के पश्चात् भारतीय दण्ड संहिता (IPC) का स्थान लिया।
 - BNS में 358 धाराएँ हैं, जो IPC की 511 धाराओं से कम हैं।
 - इसमें 20 नए अपराध शामिल किए गए हैं, 33 अपराधों के लिए कारावास की अवधि बढ़ाई गई है तथा 83 अपराधों के लिए जुर्माना बढ़ाया गया है। इसमें 23 अपराधों के लिए अनिवार्य न्यूनतम सजा और 6 अपराधों के लिए सामुदायिक सेवा की सजा भी शामिल है।
 - इसके अतिरिक्त, BNS में उन्नत प्रौद्योगिकियाँ शामिल हैं, जो दस्तावेजों की परिभाषा का विस्तार करते हुए ईमेल और सर्वर लॉग जैसे डिजिटल रिकॉर्ड को भी इसमें शामिल करती हैं।
- कानून में FIR से लेकर फैसले तक की पूरी न्यायिक प्रक्रिया को डिजिटल बनाने की अनुमति दी गई है, जिसमें आरोपी व्यक्तियों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेशी का मौजूदा प्रावधान है।

नया कानून (भारतीय न्याय संहिता, 2023)	पुराना कानून (भारतीय दण्ड संहिता 1860)
स्वतन्त्रता के पश्चात् के भारत में, आधुनिक मूल्यों को दर्शाता हुए, तैयार किया गया	ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के दौरान तैयार किया गया
सरली एवं आधुनिक भाषा	पुरातन अंग्रेजी
संशोधित संरचना, नए अनुभाग शामिल	511 अनुभाग
राष्ट्रीय सुरक्षा, साइबर अपराध, आतंकवाद पर अधिक ध्यान	देशद्रोह सम्बन्धी धाराएँ, राष्ट्रीय सुरक्षा पर कम बल
विस्तारित परिभाषाओं में साइबर स्टॉकिंग, डिजिटल उत्पीड़न शामिल	पुरानी परिभाषाएँ, आधुनिक अपराधों की सीमित पहचान
अधिक लिंग-तटस्थ प्रावधान	कुछ अनुभाग लिंग-विशिष्ट
साइबर अपराधों पर व्यापक धाराएँ	न्यूनतम सन्दर्भ
वैकल्पिक सजा सहित अद्यतन दण्ड	दण्ड के पारम्परिक रूप
पुनर्स्थापनात्मक न्याय और पीड़ित मुआवजे पर बल	सीमित प्रावधान
भ्रष्टाचार के आधुनिक स्वरूपों से निपटने के लिए विस्तृत प्रावधान	सामान्य प्रावधान
वितीय धोखाधड़ी, मनी लॉण्ड्रिंग को शामिल करने के लिए विस्तारित किया गया	बुनियादी परिभाषाएँ
अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता के विचारों के साथ संरेखित करने के लिए संशोधित	आपराधिक मानहानि शामिल
गैर-अपराधिक	दण्डनीय अपराध
सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के पश्चात इसे अपराध मुक्त कर दिया गया	धारा 377 के तहत अपराध
धर्म की स्वतन्त्रता के सम्बन्ध में अधिक सन्तुलित दृष्टिकोण	सख्त प्रावधान
मान्यता प्राप्त और अपराधीकृत	मान्यता प्राप्त नहीं
प्रौद्योगिकी और फोरेन्सिक विज्ञान पर बल देते हुए आधुनिकीकरण किया गया	पारम्परिक तरीके
विशेष प्रावधानों के साथ एकीकृत दृष्टिकोण	पृथक अधिनियम (किशोर न्याय अधिनियम, 2015)

वायरलेस मॉनिटरिंग प्रशिक्षण एवं विकास केन्द्र (WMTDC) हैं।

- संगठनात्मक सुधार समिति की सिफारिश के आधार पर संचार मन्त्री द्वारा अनुमोदित इस विलय का उद्देश्य प्रशिक्षण में एकीकरण और दक्षता को बढ़ाना है।

- NCA संसाधनों को सुव्यवस्थित करेगा, कौशल निर्माण के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण प्रदान करेगा तथा सहयोगात्मक एवं अन्तःविषयक अनुसन्धान को बढ़ावा देगा।
- NCA शिक्षण अनुभव को बेहतर बनाने के लिए साझा सुविधाओं और प्रौद्योगिकी का उपयोग करेगा।

‘संविधान हत्या दिवस’ के रूप में मनाया जाएगा 25 जून

- केन्द्र सरकार ने 12 जुलाई, 2024 को प्रतिवर्ष 25 जून को ‘संविधान हत्या दिवस’ के रूप में मनाने की घोषणा की।
- यह निर्णय वर्ष 1975 में इसी दिन पूर्व प्रधानमंत्री इन्दिरा गाँधी द्वारा आपातकाल लगाए जाने की याद में लिया गया है। इस दिवस का उद्देश्य व्यक्तिगत स्वतन्त्रता को बनाए रखना और भारत के लोकतन्त्र की रक्षा करना है।
- अमित शाह के अनुसार, आपातकाल एक तानाशाहीपूर्ण कृत्य था, जिसने भारतीय लोकतन्त्र को दबा दिया, जिसके परिणामस्वरूप बड़े पैमाने पर लोगों को जेल में डाला गया और मीडिया पर सेंसरशिप लागू की गई।
- ‘संविधान हत्या दिवस’ भारत के संविधान की अवहेलना के परिणामों की याद दिलाता है।

प्रसारण और केबल सेवाओं में संशोधन अधिसूचित

- भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (TRAI) ने 8 जुलाई, 2024 को प्रसारण और केबल सेवाओं के लिए नियामक ढाँचे में संशोधन की घोषणा की।
- TRAI ने 200 चैनलों के लिए ₹ 130 तथा 200 से अधिक चैनलों के लिए ₹ 160 की नेटवर्क क्षमता शुल्क (NCF) की अधिकतम सीमा को हटा दिया, जिससे शुल्क का निर्धारण बाजार की शक्तियों द्वारा किया जा सकेगा।
- पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए, TRAI ने अनिवार्य किया कि सेवा प्रदाता सभी शुल्कों को प्रकाशित करें, उपभोक्ताओं को सूचित करें तथा नियामक को रिपोर्ट करें। इन संशोधनों का प्राथमिक उद्देश्य प्रसारण क्षेत्र के विकास को सुविधाजनक बनाना तथा विनियामक प्रावधानों को सरल बनाकर व्यापार को आसान बनाना है।

BIS ने इलेक्ट्रिक वाहनों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए पेश किए 2 नए मानक

- भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) ने 23 जून, 2024 को इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) की सुरक्षा बढ़ाने के उद्देश्य से 2 नए मानक, IS 18590: 2024 और IS 18606: 2024 पेश किए हैं।
- ये मानक विशेष रूप से EV पावरट्रेन और बैटरियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जो महत्वपूर्ण घटक हैं, जो प्रदर्शन और सुरक्षा दोनों को निर्धारित करते हैं।
- वे L, M और N श्रेणी के इलेक्ट्रिक वाहनों पर लागू होते हैं तथा बैटरियों के लिए कड़ी सुरक्षा आवश्यकताओं और मजबूत प्रदर्शन मानकों पर बल देते हैं।

- यह पहल इलेक्ट्रिक वाहनों की विश्वसनीयता और सुरक्षा को मजबूत करने, उनकी दक्षता एवं समग्र सुरक्षा में योगदान देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

‘सफाई अपनाओ-बीमारी भगाओ’ पहल का शुभारम्भ

- आवास एवं शहरी मामलों के मन्त्रालय ने 25 जून, 2024 को स्वच्छ भारत मिशन-शहरी 2.0 के अन्तर्गत ‘सफाई अपनाओ, बीमारी भगाओ’ पहल शुरू करने की घोषणा की। यह पहल 1 जुलाई-31 अगस्त, 2024 तक चली।
- इस पहल का उद्देश्य जून से अगस्त की अवधि के दौरान भारी वर्षा और बढ़े हुए स्वास्थ्य जोखिमों से उत्पन्न चुनौतियों का प्रबंधन करने के लिए शहरी स्थानीय निकायों की तत्परता को मजबूत करना था।
- यह स्वास्थ्य मन्त्रालय के ‘STOP डायरिया अभियान’ के अनुरूप था तथा जिसमें मानसून के मौसम में स्वच्छता और स्वास्थ्य चुनौतियों से निपटने के लिए मन्त्रालयों के मध्य सहयोग को बढ़ावा देना था।

उपराष्ट्रपति द्वारा ‘प्रेरणा स्थल’ का उद्घाटन

- राज्य सभा के सभापति और उपराष्ट्रपति के रूप में कार्यरत जगदीप धनखड़ ने 17 जून, 2024 को संसद भवन परिसर में ‘प्रेरणा स्थल’ का उद्घाटन किया।



- यह नव स्थापित स्थल राष्ट्रीय प्रतीकों और स्वतन्त्रता सेनानियों की प्रतिमाओं को एकीकृत करता है, जो पहले परिसर में विभिन्न स्थानों पर बिखरी हुई थीं।
- ‘प्रेरणा स्थल’ का उद्देश्य इन प्रतिमाओं तक आगंतुकों की पहुँच में सुधार करना और भारतीय इतिहास को इन प्रभावशाली हस्तियों की जीवन कहानियों को व्यक्त करने के लिए QR कोड जैसी समकालीन तकनीक का उपयोग करना है।

IGI हवाई अड्डे पर पहला फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन-TTP कार्यक्रम

- केन्द्रीय गृह मन्त्री अमित शाह ने 22 जून, 2024 को नई दिल्ली के इन्दिरा गाँधी अन्तर्राष्ट्रीय हवाई

अड्डे पर फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन ट्रस्टेड ट्रैवलर कार्यक्रम (FTI-TTP) का उद्घाटन किया।

- यह पहल भारतीय नागरिकों और ओवरसीज सिटीजन ऑफ इण्डिया कार्डधारकों के लिए तैयार की गई है, जिसका उद्देश्य उनकी यात्रा प्रक्रिया को सरल बनाना है।
- पात्र व्यक्ति ऑनलाइन आवेदन करेंगे, बायोमेट्रिक डेटा उपलब्ध कराएंगे तथा अन्य आवश्यक जानकारी प्रस्तुत करेंगे।
- पात्रता मानदण्डों के सत्यापन और पुष्टि के बाद पंजीकरण को अन्तिम रूप दिया जाएगा। प्रोसेसिंग शुल्क का भुगतान करने के पश्चात्, आवेदनों पर कार्रवाई की जाएगी।
- FTI-TTP का उद्देश्य दक्षता, सुविधा और सुरक्षा उपायों को बढ़ाकर यात्रियों के यात्रा अनुभव को आधुनिक और त्वरित बनाना है।

PMAY के अन्तर्गत 3 करोड़ अतिरिक्त घरों की घोषणा

- प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 12 जून, 2024 को ‘प्रधानमंत्री आवास योजना’ (PMAY) के अन्तर्गत अतिरिक्त 3 करोड़ ग्रामीण और शहरी घर उपलब्ध कराने के निर्णय की घोषणा की।
- PMAY-G के अन्तर्गत लाभार्थियों को मैदानी इलाकों में ₹ 1.2 लाख और पहाड़ी, दुर्गम, आदिवासी तथा पिछड़े क्षेत्रों में ₹ 1.3 लाख की सहायता मिलती है। सरकार की योजना इस सहायता को लगभग 50% बढ़ाने की है।
- मैदानी क्षेत्रों में PMAY-G आवास निर्माण की लागत ₹ 1.2 लाख से बढ़कर ₹ 1.8 लाख हो गई तथा पहाड़ी क्षेत्रों में ₹ 1.3 लाख से बढ़कर ₹ 2 लाख हो गई।
- इस समायोजन का उद्देश्य लाभार्थियों को बेहतर आवास सहायता उपलब्ध कराना है।

‘एक पेड़ माँ के नाम’ अभियान का शुभारम्भ

- प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 5 जून, 2024 को दिल्ली के बुद्ध जयन्ती पार्क में पीपल का पौधा लगाकर विश्व पर्यावरण दिवस मनाने के लिए ‘एक पेड़ माँ के नाम’ अभियान का उद्घाटन किया। इस अवसर पर केन्द्रीय पर्यावरण मन्त्री भूपेन्द्र यादव और दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना भी शामिल हुए।
- वृक्षारोपण का कार्य प्रकृति की रक्षा और दीर्घकालिक जीवन को बढ़ावा देने के प्रति भारत की प्रतिबद्धता का प्रतीक है।
- पिछले दशक में, भारत ने सम्पूर्ण देश में वन क्षेत्र बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण सामूहिक प्रयास किए हैं, जो सतत विकास के प्रति देश के समर्पण को दर्शाता है।

• यह भी उल्लेखनीय है कि स्थानीय समुदायों ने किस प्रकार सक्रिय रूप से भाग लिया और इन पर्यावरणीय पहलों में अग्रणी भूमिका निभाई तथा राष्ट्र के हरित लक्ष्यों में महत्वपूर्ण योगदान दिया।

केन्द्र सरकार द्वारा नई मोबाइल नम्बर सीरीज की शुरुआत

- केन्द्र सरकार ने 3 जून, 2024 को सेवा या लेन-देन सम्बन्धी कॉलों के लिए एक नई नम्बरिंग श्रृंखला, 160xxxxxxx, शुरू की।
- इस कार्रवाई का उद्देश्य 10 अंकों वाले मोबाइल नम्बरों का उपयोग करने वाले टेलीमार्केटर्स से आने वाली अवांछित वॉयस कॉल को कम करना तथा वैध कॉलों की शीघ्र पहचान करने में नागरिकों सहायता करना है।
- टेलीमार्केटर्स को लेन-देन, सेवा और प्रचार सम्बन्धी कॉलों के लिए 140xxxxxxx श्रृंखला सौंपी गई है।
- हालांकि, उपभोक्ता अक्सर इन कॉलों को नजर-अन्दाज कर देते हैं, क्योंकि इनका उपयोग अक्सर प्रचार उद्देश्यों के लिए किया जाता है, जिसके कारण वे महत्वपूर्ण सेवा और लेन-देन सम्बन्धी सम्पर्कों से चूक जाते हैं।
- दूरसंचार विभाग ने घोषणा की है कि प्रमुख संस्थाएँ केवल नई 160xxxxxxx श्रृंखला पर ही सेवा और लेन-देन सम्बन्धी कॉल करेंगी।

गृह मन्त्रालय की संचार साथी पहल

- दूरसंचार विभाग और गृह मन्त्रालय ने फर्जी SMS से निपटने के लक्ष्य के साथ 29 मई, 2024 को संचार साथी पहल शुरू की।
- इस कार्यक्रम का उद्देश्य भ्रामक सन्देशों के प्रसार को सम्बोधित करना है जो भोले-भाले मोबाइल उपयोगकर्ताओं को शिकार बनाते हैं।
- विशेष रूप से, धोखेबाजों द्वारा आमतौर पर उपयोग किये जाने वाले 8 SMS हेडर पाए गए हैं, जो सरकार द्वारा ब्लैकलिस्ट किए गए हैं।
- दूरसंचार विभाग ने पिछले 3 महीनों में 8 अलग-अलग स्रोतों से आए करीब 10000 फर्जी मेल पकड़ी हैं।
- दूरसंचार विभाग ने कड़ी कार्रवाई करते हुए इन अवैध गतिविधियों को रोकने के लिए इन व्यवसायों से जुड़े 1522 SMS कण्टेन्ट टेम्प्लेट और 73 SMS हेडर को ब्लॉक कर दिया है।

CSC के माध्यम से ई-माइग्रेट सेवाएँ

- विदेश मन्त्रालय, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मन्त्रालय एवं कॉमन सर्विसेज सेण्टर्स ई-गवर्नेन्स सर्विसेज इण्डिया लिमिटेड द्वारा 29 मई, 2024 को सम्पूर्ण देश में ई-माइग्रेट

सेवाओं की पेशकश करने की योजना की रूपरेखा तैयार करते हुए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।

- ई-माइग्रेट परियोजना के लिए प्राथमिक लक्षित दर्शक ब्लू-कॉलर कार्यकर्ता हैं, जो आवश्यक आब्रजन जाँच वाले देशों में प्रवास कर रहे हैं।
- इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मन्त्रालय के अनुसार, परियोजना को सुरक्षित और वैध प्रवासन की सुविधा के लिए विदेशी नियोक्ताओं, बीमा कम्पनियों और पंजीकृत भर्ती एजेंटों को एक मंच पर लाने के लिए डिजाइन किया गया था।

खाद्य एवं पोषण बोर्ड भंग

- कई संगठनों को सुव्यवस्थित करने के सरकार के प्रयास के अन्तर्गत खाद्य और पोषण बोर्ड (FNB) को 27 मई, 2024 को औपचारिक रूप से भंग कर दिया गया।
- महिला और बाल विकास मन्त्रालय (WCD) का खाद्य और पोषण बोर्ड (FNB) एक तकनीकी प्रभाग है जो सामुदायिक पोषण कार्यक्रमों को तार्किक रूप से समर्थन देने का कार्य करता है।
- महिला एवं बाल विकास मन्त्रालय द्वारा जारी एक बयान के अनुसार, FNB, जो फरीदाबाद, मुम्बई, कोलकाता और चेन्नई जैसे प्रमुख शहरों के आसपास 4 क्षेत्रीय कार्यालयों और कई गुणवत्ता नियन्त्रण प्रयोगशालाओं वाले कार्यालयों का एक विशाल नेटवर्क चलाता था, को भंग कर दिया गया था।

इंडियास्किल्स कम्पटीशन 2024 आयोजित

- देश की सबसे बड़ी कौशल प्रतियोगिता, द इण्डियास्किल्स कम्पटीशन 2024, जिसका उद्देश्य स्किलिंग के उच्चतम मानकों को प्रदर्शित करना था, 15 मई, 2024 को शुरू हुआ।
- यशोभूमि, द्वारका, नई दिल्ली में आयोजित एक उद्घाटन समारोह में, 30 से अधिक राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों के 900 से अधिक छात्रों के साथ-साथ 400 से अधिक उद्योग विशेषज्ञों ने इसमें भाग लिया।
- 4 दिवसीय इण्डिया स्किल्स इवेन्ट के माध्यम से, प्रतिभागी पारम्परिक शिल्प से लेकर अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों तक 61 प्रतिभागियों के साथ एक राष्ट्रीय मंच पर अपनी व्यापक क्षमताओं और प्रतिभा का प्रदर्शन करने में सक्षम हुए।
- उपलब्ध सर्वोत्तम बुनियादी ढांचे को ध्यान में रखते हुए ऑनसाइट आयोजित की जाने वाली 47 कौशल प्रतियोगिताओं के अतिरिक्त, गुजरात, कर्नाटक, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में 14 कौशल प्रतियोगिताएं ऑफसाइट आयोजित की गयीं।

सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अरावली में खनन के नए पट्टे देने पर रोक

- सर्वोच्च न्यायालय ने 10 मई, 2024 को 4 राज्यों को अरावली में नए खनन पट्टे देने से प्रतिबंधित कर दिया।
- 4 राज्य जहाँ अरावली लोग रहते हैं- दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा और गुजरात- न्यायालय के फैसले के दायरे में आते हैं।
- केन्द्रीय अधिकार प्राप्त समिति (CEC) के अध्ययन में कहा गया है कि अरावली में पहाड़ियाँ हैं और पहाड़ियों के चारों ओर एक सुसंगत बफर जोन है, जो 100 मी चौड़ा है।
- न्यायालय ने इस बात पर बल दिया कि उसके फैसले को उन खनन कार्यों पर प्रतिबन्ध के रूप में नहीं माना जाएगा, जो वर्तमान में वैध परमिट और लाइसेंस के अंतर्गत सीमा के भीतर चल रहे हैं।
- यह पारिस्थितिकी तन्त्र की रक्षा और खनन में शामिल व्यक्तियों के लिए आजीविका के साधन बनाए रखने के मध्य सन्तुलन बनाए रखने के लिए किया गया था।

भारतीय ऐतिहासिक रिकॉर्ड आयोग के लिए नया प्रतीक और लोगो

- भारतीय ऐतिहासिक रिकॉर्ड आयोग ने 25 अप्रैल, 2024 को एक नया प्रतीक और उद्देश्य अपनाया।
- वर्ष 1919 में स्थापित IHRC का नेतृत्व केन्द्रीय संस्कृति मन्त्री करते हैं। यह प्रतीक IHRC की थीम और मौलिकता को सम्पूर्ण रूप से दर्शाता है।
- कमल की पंखुड़ियों के आकार वाले पृष्ठ, IHRC को ऐतिहासिक दस्तावेजों को संरक्षित के लिए एक दृढ़ नोडल संगठन के रूप में दर्शाते हैं। मध्य में सारनाथ स्तम्भ भारत की समृद्ध विरासत का प्रतीक है।

‘रन फॉर सन’ मैराथन का आयोजन

- भारत सरकार ने सम्पूर्ण विश्व के साथ 3 मई, 2024 को इण्टरनेशनल सन डे मनाया, जो एक हरित और स्वस्थ ग्रह को बढ़ावा देने में सौर ऊर्जा के प्रमुख लाभों का एक वार्षिक अनुस्मारक है।
- नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में, भारत सरकार के नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE) ने इस दिन ‘रन फॉर सन’ मैराथन की मेजबानी की।
- ‘रन फॉर सन’ मैराथन का उद्देश्य जलवायु परिवर्तन को कम करने और सभी के लिए एक स्वच्छ, स्वस्थ भविष्य को आगे बढ़ाने में सौर ऊर्जा की महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में सार्वजनिक जागरूकता बढ़ाना है।

NSDC और ISKCON का जनजातीय कौशल विकास के लिए सहयोग

- ISKCON और NSDC भारत में आदिवासी और गरीब युवाओं को व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए मिलकर कार्य करेंगे।
- साझेदारी का प्रारंभिक केन्द्र उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश थे, जिसका उद्देश्य वंचित लोगों को व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करना था।
- इस रणनीतिक समझौते के अन्तर्गत अल्पकालिक पाठ्यक्रम पेश किए जाएंगे, जो स्किल इण्डिया डिजिटल हब प्लेटफॉर्म के माध्यम से उद्योग-मान्यता प्राप्त क्रेडेन्शियल्स प्रदान करेंगे।
- इसका उद्देश्य रोजगार में सुधार करना और सिखाए गए व्यक्तियों को NSDC इंटरनेशनल के माध्यम से घरेलू और अन्तर्राष्ट्रीय कार्य संभावनाओं तक पहुँच प्रदान करना था।

शोम्पेन जनजाति ने चुनाव में पहली बार किया मतदान

- भारत के विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (PVTGs) में से एक, शोम्पेन जनजाति ने 23 अप्रैल, 2024 को अण्डमान और निकोबार लोकसभा सीट पर मतदान किया, इस प्रकार उन्होंने पहली बार अपने लोकतान्त्रिक अधिकार का प्रयोग किया।
- वर्ष 2011 की जनगणना के आँकड़ों के अनुसार, शोम्पेन जनजाति के लगभग 229 लोग हैं।
- अण्डमान और निकोबार लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र ने कुल 63.99% मतदान हासिल किया, जो वर्ष 2019 के चुनावों में हुए 65.09% मतदान से मामूली कम था। चुनाव प्रक्रिया में शोम्पेन जनजाति की भागीदारी बेहद महत्वपूर्ण है।

LGBTQ कल्याण के लिए समिति नियुक्त

- केन्द्र सरकार ने 20 अप्रैल, 2024 को LGBTQ सामुदायिक कल्याण के लिये एक समिति की स्थापना की।
- महत्वपूर्ण मन्त्रालयों के सचिवों सहित समूह के 6 सदस्यों का नेतृत्व केन्द्रीय गृह सचिव राजीव गौबा करेंगे।
- समिति का मुख्य लक्ष्य उन नीतियों के लिए सिफारिशें करना है जो विभिन्न सन्दर्भों में LGBTQ+ व्यक्तियों के विरुद्ध भेदभाव को समाप्त करेंगी।
- इसमें जबरन चिकित्सा प्रक्रियाओं या उपचारों को समाप्त करना, सुरक्षा सावधानियों में सुधार करना, उत्पादों एवं सेवाओं तक समान पहुँच की गारण्टी देना, और सामाजिक कल्याण लाभों में असमानताओं को हल करना शामिल है।

विदेशी प्रबन्धन अधिनियम के अन्तर्गत संशोधन नियम अधिसूचित

- अन्तरिक्ष क्षेत्र के लिये 100% FDI तक की अनुमति देने के अपने निर्णय को क्रियान्वित करने के लिये सरकार ने 18 अप्रैल, 2024 को विदेशी मुद्रा प्रबन्धन अधिनियम के अन्तर्गत नए दिशानिर्देश जारी किये।
- उपग्रहों का उत्पादन और संचालन, उपग्रह डेटा उत्पाद, ग्राउण्ड सेगमेंट और उपयोगकर्ता सेगमेंट सभी 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए पात्र हैं।
- जिसमें 74% से अधिक निवेश के लिए सरकार की अनुमति की आवश्यकता होगी। कुल निवेश का 74% तक स्वचालित विधि के माध्यम से जाएगा।
- अन्तरिक्ष यान लैंडिंग और टेकऑफ के लिए स्पेसपोर्ट के विकास के साथ-साथ लॉन्च वाहनों और सम्बन्धित प्रणालियों या उप-प्रणालियों के लिए स्वचालित FDI के माध्यम से 49% तक धन भी उपलब्ध कराया गया है।

राष्ट्रीय प्रसारण नीति के निर्माण पर परामर्श पत्र

- भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (TRAI) द्वारा 2 अप्रैल, 2024 को राष्ट्रीय प्रसारण नीति-2024 के निर्माण के सुझावों पर एक परामर्श पत्र जारी किया गया।
- नीति-निर्माण प्रक्रिया में उपयोग किए गए इनपुट का उद्देश्य रणनीतिक विस्तार और उन्नति के लिए लक्ष्यों, योजनाओं एवं रणनीतियों को परिभाषित करना है।
- इस परामर्श पत्र में भारत को विषय-वस्तु के लिए एक वैश्विक केन्द्र के रूप में स्थापित करने के उद्देश्य से उन महत्वपूर्ण सरोकारों की पहचान की गई है, जो सामान्यतः प्रसारण उद्योग में विद्यमान हैं।
- दस्तावेज सार्वजनिक सेवा प्रसारण में सुधार करने, विभिन्न मीडिया और मनोरंजन क्षेत्रों के

साथ समस्याओं से निपटने, पायरेसी को रोकने और सामग्री सुरक्षा की गारण्टी देने के तरीके को सम्बोधित करता है।

ग्रेट इण्डियन बस्टर्ड संरक्षण के लिए समिति नियुक्त

- सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चन्द्रचूड़ ने 26 मार्च, 2024 को ग्रेट इण्डियन बस्टर्ड के गम्भीर खतरे से निपटने के लिए एक विशेषज्ञ समिति नियुक्त की। जिसमें संरक्षण को संतुलित करने की आवश्यकता पर बल दिया गया है।
- गुजरात और राजस्थान में, शक्तिशाली विद्युत तारों के साथ टकराव से ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की आबादी विलुप्त हो सकती है।
- सुप्रीम कोर्ट ने पक्षियों की प्रजातियों की सुरक्षा के लिए भूमिगत विद्युत तारों के अपने आदेश पर पुनर्विचार किया है। समिति वन्यजीव, विशेषज्ञ, पर्यावरणविद और सम्बन्धित विभागों के सरकारी अधिकारी शामिल हैं।

सरकार के विरुद्ध फर्जी खबरों की पहचान करने के लिए एक फैक्ट-चेकिंग यूनिट

- केन्द्र सरकार ने 20 मार्च, 2024 को सोशल मीडिया पर सरकार के विरुद्ध किसी भी फर्जी खबर पर नजर रखने के लिए फैक्ट-चेकिंग टीम की स्थापना की घोषणा की।
- यह घोषणा बॉम्बे हाईकोर्ट द्वारा कॉमेडियन कुणाल कामरा के FCU की स्थापना को रोकने के अस्थायी अनुरोध को अस्वीकार करने के कुछ दिनों बाद की गई थी।
- IT नियमों के अनुसार, FCU को किसी भी पोस्ट के सोशल मीडिया मध्यस्थों को सूचित करना आवश्यक है जो भ्रामक हैं।
- यह धोखाधड़ी, गलत या सरकारी कार्यों से सम्बन्धित भ्रामक जानकारी के बारे में भी रिपोर्ट करेगा।

‘वन व्हीकल, वन फास्टैग’ लागू

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) द्वारा 1 अप्रैल, 2024 को ‘वन व्हीकल, वन फास्टैग’ मानक लागू किया गया। इसका लक्ष्य लोगों के कई फास्टैग्स को एक साथ जोड़ने या कई कारों के लिए एक फास्टैग (FASTag) का उपयोग करने से रोकना है।

NHAI ने पेटीएम फास्टैग उपयोगकर्ताओं को होने वाली समस्याओं को देखते हुए पहले ही अनुपालन की समय सीमा मार्च के अन्त तक बढ़ा दी थी। ‘वन व्हीकल, वन फास्टैग’ अभियान का उद्देश्य इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह प्रणाली की प्रभावशीलता में सुधार करना और टोल प्लाजा पर सुचारु यातायात की गारंटी देना है।

